Drought-Affected Areas

298. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the areas identified as drought affected/drought prone in different States;

(b) whether any specific region in the State of orissa has been declared as drought-affected;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken to help the farmers?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) 947 Blocks in 149 districts of 13 States spread over 7.46 lakh square Kilometers have been identified as drought prone in the country under the Drought Prone Areas Programme.

(b) and (c) According to initial reports received from the Govt. of Orissa, 26701 villages in 26 districts have suffered crop loss of 50% and above. Relief measures have been undertaken in the affected areas.

(d) The State Government has mounted a massive Rabi Programme with a view to recoup the losses in Kharif. As part of the Programme the State Government proposes to provide agricultural input subsidy to the affected farmers.

"वनाच्छादित भूमि"

299. **श्री रामजीलाल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितना भूमि क्षेत्र वनाच्छादित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान काटे गये और नये लगाये गये वृक्षों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) स्टेट आफ फोरस्ट रिपोर्ट, 1995 के अनुसार देश में 1995 के मूल्यांकन के अनुसार कुल वनावरण 6,39,600 वर्ग कि॰ मी॰ क्षेत्र अर्थात् देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.46 प्रतिशत है। वनावरण का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) सरकारी वन भूमि तथा गैर सरकारी वन भूमि में कांटे गए वृक्षों के बारे में सूचना राज्य स्तर पर रखी जाती है। सरकारी वन भूमि सहित कुल 27.69 लाख हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि में वनीकरण किया गया है और पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक भूमि के अलावा पौधरोपण के लिए कुल 34.576,11 लाख पौध वितरित की गई।

(ग) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम और इसके परिणाम विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

वनाच्छादित भूमिक्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा

राज्यवार वनावरण (वर्ग कि॰मी॰ में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995 का मूल्यांकन
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.112
2.	अरूणाचल रदेश	68,621
3.	असम	24,061
4.	बिहार	26,561
5.	दिल्ली	26
6.	गोवा, दमन और द्वीव	1,250
7.	गुजरात	12,320
8.	हरियाणा	603
9.	हिमाचल प्रदेश	12,501
10.	जम्मू व कश्मीर	20,433
11.	कर्नाटक	32,382
12.	केरल	10,336
13.	मध्य प्रदेश	1,35,164
14.	महाराष्ट्र	43,843
15.	मणिपुर	17,558

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995 का मूल्यांकन
16.	मेघालय	15,714
17.	मिजोरम	18,576
18.	नागालैण्ड	14,291
19.	उड़ीसा	47,107
20.	पंजाब	1,342
21.	राजस्थान	13,280
22.	सिक्किम	3,127
23.	तामिलनाडु	17,766
24.	त्रिपुरा	5,538
25.	उत्तर प्रदेश	33,986
26.	पश्चिम बंगाल	8,276
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7,615
28.	चंडीगढ़	7
29.	दादर और नगर हवेली	204
30.	लक्षद्वीप	—
31.	पांडिचेरी	—
	कुल	639,600

कोई वन दिखाई नहीं देते

विवरण-II

प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए उठाए गए कदम और इसके परिणाम

पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए तथा प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शमिल हैं:

1. देश के बड़े शहरों और नगरों में मोटर-वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक बड़ा यानीय सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का प्रयोग बड़े शहरों के यानीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपाय तैयार करने हेतु किया गया
2. वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बड़े सैक्टरों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित मानकों का अनुपालन करें।
3. केन्द्रीय मोटर-वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है।
4. देश भर में आपूर्ति किए जाने वाले पेट्रोल में दिसम्बर, 1996 तक पेट्रोल में सीसे के स्तर को प्रति लीटर 0.5 ग्राम तक कम करने की योजना है।
5. सीसा रहित पेट्रोल चार पहिए वाले पेट्रोल चालित वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर शुरू करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम-चरणबद्ध रूप से कार्यन्वित किया जा रहा है।
6. कुछ शहरों में पेट्रोल चालित वाहनों में सम्पीडित प्राकृतिक गैस शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
7. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम चल रही हैं।
8. बड़ी नदियों के प्रदूषित भागों की सफाई के लिए राष्ट्रीय नदी कार्यवाही योजना तैयार की गई है जिसमें बड़े शहरों और नगरों की नगरपालिकाओं को शामिल किया गया है। द्वितीय चरण में गंगा कार्यवाही योजना में यमुना नदी की सफाई भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के पास दिल्ली में मलजल शोधन संयंत्रों में वृद्धि करने का एक बड़ा कार्यक्रम है।
9. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों की सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।
10. स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाकर स्रोत पर प्रदूषण नियंत्रण पर बल दिया गया है।
11. उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्फलों का गठन किया गया है और वेहतर हाउस कीपिंग तथा उत्तम कार्य पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया है।
12. 29 विशिष्ट श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली प्रस्तावित वही विकास गतिविधियों को पर्यावरणीय प्रमुख मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के तहत

पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी लेनी अपेक्षित हैं।

Eco-Development in Reserved Areas

300. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether five protected areas — five tiger reserve, one elephant park and Gir forest for Asiatic lion — have been selected in the country for eco-development in these reserved areas;

(b) if so, the names of the areas and the total cost involved in the project;

(c) the amount to be contributed by different organisations/bodies for the project with names of each contributor;

(d) whether the local people of these areas will be associated in the implementtion of this project; if so, the details thereof; and

(e) whether interests of the people of these areas like tribals will be protected, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) and (b) Yes, Sir. The seven protected areas selected under the project are — Palamau Tiger Reserve (Bihar), Gir National Park (Gujarat), Nagarhole National Park (Karnataka), Periyar Tiger Reserve (Kerala), Pench Tiger Reserve (Madhya Pradesh), Ranthambhore Tiger Reserve (Rajasthan) and Buxa Tiger Reserve (West Bengal). The total cost of the project is US 67 Million.

(c) Out of the total project cost of US $ 67 million, $ 20 million will come from Global Environmental Facility (GEF) grant; US $ 28 million from International Development Agency (IDA) credit; US $ 15 million will be contributed by the Government of India and the State Government concerned; with the balance amount of US $ 4 million to be contributed by the beneficiaries in the from of labour.

(d) and (e) Yes, Sir. It is mandatory under the project to constitute Eco-development Committee for each village representing atleast one member from each family of the village and the proposed eco-development works will be finalised by the same Committee after microplanning. Therefore, the interests of the local people including tribals will be safeguarded.

Income of Indian Railway from Waste Materials

301. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the details of annual income to Indian Railways from the sale of waste materials like railway scraps;

(b) the details of those who generally buy these scraps;

(c) whether there is any rule set for selling these materials and also for a buyer to be eligible for buying such materials; and

(d) whether any inventory has been maintained of the scraps; if so, the quantitites of scraps available, zone-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a), The total value of scrap sale was Rs. 1018/- crores during 1995-96 on the Indian Railways.

(b) and (c) As per prescribed policy, Railway scrap material is desposed of through open auction/tender sale for which set rules and procedures have been laid down in the Indian Rail ways Stroes Code. The action/tender sale programme is notified through leading newspapers for public information and anybody who fulfils the general conditions can participate in the auction/tender sale.

(d) Yes, Sir. A statment is attached.